



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2015/ आषाढ़ 31, 1937

No. 199]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2015/ASADHA 31, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2015

(निर्णायक समीक्षा)

चीन जन. गण. और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बैम्बू फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

सं. 15/9/2015-डीजीएडी - 1995 में और उसके बाद यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. और इंडोनेशिया (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित " बैम्बू फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर " (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

2. यतः संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जाँच प्राधिकारी द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/6/2009-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी और प्राधिकारी द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. 14/6/2009-डीजीएडी द्वारा प्रारंभिक जाँच परिणाम प्रकाशित किए गए थे। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम दिनांक 17 मई, 2010 की अधिसूचना सं. 14/6/2009-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किए गए थे और केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या 76/2010-सीमा शुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

3. यतः, वर्तमान याचिका विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की ओर से एसोसिएशन ऑफ़ मैन-मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ़ इंडिया (जिन्हें इसके बाद याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा दायर की गई है। इसके एक सदस्य मैं ग्रासिम इंडस्ट्री लि. जोकि सोल कंपनी है (जिसे इसके बाद याचिकाकर्ता कंपनी कहा गया है)। याचिकाकर्ता ने चीन जन. गण. और इंडोनेशिया (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है)

है) से " बैम्बू फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर "(जिसे एतदपश्चात् वीएसएफ या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की अवधि को बढ़ाने, उसमें संशोधन करने और उसे बढ़ाने के लिए इस आवेदन में संगत वित्तीय सूचना प्रस्तुत की है। यह याचिका निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके के अनुसार है।

शामिल देश

4. इस जाँच में शामिल देश चीन जन. गण. और इंडोनेशिया हैं।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद " बैम्बू फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर " है। यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण के अध्याय 55 के अंतर्गत सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं 550410 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक प्रकृति का है और जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. प्राधिकारी ने मूल जाँच के अंतिम जाँच परिणाम में निम्नानुसार नोट किया है,

"विचाराधीन उत्पाद " बैम्बू फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) " है। विस्कोस स्टेपल फाइबर को सीमाशुल्क टैरिफ के अंतर्गत विस्कोस रेयान स्टेपल फाइबर कार्डेड या काम्ब्ड नहीं के रूप में वर्णित किया जाता है और कुछ बाजारों में "रेयान फाइबर" के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क शीर्ष सं 5504.10.00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है। विस्कोस स्टेपल फाइबर पहला मानव-निर्मित फाइबर था और अन्य मानव-निर्मित फाइबर से इतर यह सिंथेटिक फाइबर नहीं है। इसे वेट स्पिनिंग प्रौद्योगिकी के जरिए बनाया जाता है और यह वुड पल्प से निर्मित पुनः समेकित सेल्युलोज फाइबर है, जो सततपोषणीय प्राकृतिक संसाधन अर्थात् लकड़ी को विभिन्न रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा निकाले गए अनिवार्य सेल्युलोज से बनाया जाता है। इसके सेल्युलोज आधार के कारण विस्कोस स्टेपल फाइबर की विशेषताएं थर्मोप्लास्टिक, पेट्रोलियम आधारित सिंथेटिक फाइबरों जैसे नायलॉन या पालिएस्टर आदि की तुलना में प्राकृतिक सेल्युलोज फाइबरों से अधिक समान होती हैं। इसके अलावा सुनियोजित विनिर्देशन और एकरूपता इसकी अन्य विशेषता है। विस्कोस स्टेपल फाइबर में अत्यंत अच्छे ड्रेप के साथ रेशम जैसी सुंदरता होती है, सॉफ्ट फील है और सम्पन्न सुंदर रंग हैं। इससे बने फेब्रिक नमी सोखते हैं (कपास से भी अधिक), हवादार, पहनने में आरामदायक और सुस्पष्ट रंगों में आसानी से रंगने योग्य होते हैं। ये स्थिर विद्युत नहीं बनाते और रूखा रोधी होते हैं।

वीएसएफ की मुख्य विशेषता उसकी बहुप्रयोज्यता और चमक, मुलायम, अवशोषी बनाने के लिए लगभग सभी अन्य वस्त्र फाइबरों के साथ उसके आसानी से मिश्रित हो जाने की क्षमता है और इसके फलस्वरूप ऐसे मिश्रण से निर्मित कपड़े का आराम मिलता है। बैम्बू फाइबर जो विस्कोस स्टेपल फाइबर का एक प्रकार है, को इस जाँच के दायरे से बाहर रखा गया है। जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों से बैम्बू फाइबर को बाहर रखने के संबंध में अनुरोध करने के लिए कहा है। किसी भी हितबद्ध पक्ष ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

चूंकि प्रस्तावित जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जाँच के समान ही है।

समान वस्तु

7. समान वस्तु के संबंध में नियम 2 (घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"समान वस्तु" का अर्थ ऐसी वस्तु है जो भारत में पाटित किए जाने की जाँच के अधीन वस्तु के सभी तरह से समान यह उसके जैसी हो या ऐसी किसी वस्तु की अनुपस्थिति में कोई अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी तरह से समान नहीं हो, तथापि उसमें जाँच के अधीन वस्तु से बिल्कुल मिलती-जुलती विशेषताएं हों।

8. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और भारतीय उद्योग के द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पादों में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं।

घरेलू उद्योग और उसकी योग्यता

9. मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लि. ने घरेलू उद्योग के रूप में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है। आवेदक विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र भारतीय उत्पादक है। जैसा कि याचिकाकर्ता कंपनी ने बताया है उन्होंने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। तथापि, याचिकाकर्ता कंपनी समूह के पास चीन और इंडोनेशिया (बिरला जिंगवाई फाइबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन और पीटी इंडो भारत रेयान, इंडोनेशिया) सहित विभिन्न देशों में उत्पादन का ढांचा है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों में संबंधित निर्यातकों द्वारा भारत को कोई निर्यात नहीं किए गए हैं। अतः प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता कंपनी को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 के अनुसार वह योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

10. यतः, विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जाँच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की आशंका है, के लिए निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करते हैं।

जाँच अवधि

11. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015 (12 महीने) तक की है। तथापि, क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2011 - मार्च 2012, अप्रैल 2012 - मार्च 2013, अप्रैल 2013 - मार्च 2014 और जाँच अवधि की समयावधि शामिल होगी। जाँच अवधि के बाद के आकड़ों की भी पाटन और क्षति की आशंका के निर्धारण के लिए जाँच की जा सकती है।

प्रक्रिया

12. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 17 मई, 2010 की अधिसूचना सं. 14/6/2009-डीजीएडी (मूल जाँच के अंतिम जाँच परिणाम) द्वारा प्रकाशित मूल जाँच के अंतिम जाँच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं।
13. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:-

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उक्त अनुरोध का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा।

समय-सीमा

16. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस समीक्षा जाँच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप से अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए और उनके साथ उनकी सॉफ्ट कॉपीयों होनी चाहिए।

19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां सॉफ्ट प्रतियों के साथ, प्रस्तुत की जानी चाहिए।

20. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु; सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।

21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार का उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2015

(Sunset Review)

Initiation of Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on imports of Viscose Staple Fibre excluding Bamboo Fibre, originating in or exported from China PR and Indonesia.

F. No. 15/9/2015-DGAD - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of "Viscose Staple Fibre excluding Bamboo Fibre" (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR and Indonesia (hereinafter referred to as the subject country).

2. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries was initiated by the Authority vide Notification No. 14/6/2009- DGAD dated 19th March 2009 and preliminary finding was published by the Authority vide Notification No. 14/6/2009-DGAD dated 5th August 2009. The final finding was published by the

Authority vide Notification No. 14/6/2009-DGAD dated 17th May 2010 and definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 76/2010 dated 26th July 2010.

3. Whereas, the present petition has been filed by Association of Man-Made Fibre Industry of India (*hereinafter referred to as Petitioner*), on behalf of the domestic industry for the product under consideration. One of its members, M/s. Grasim Industries Ltd. is the sole producer (*hereinafter referred to as Petitioner Company*). The petitioner has provided relevant financial information to file this application for the extension of period, modification and enhancement of existing anti dumping duties on imports of Viscose Staple Fibre excluding Bamboo Fibre (*hereinafter referred to as VSF or subject good*) from China PR and Indonesia (*hereinafter referred to as subject countries*). The petition is in the form and manner prescribed by the Designated Authority.

Country involved

4. The countries involved in this investigation are China PR and Indonesia.

Product under Consideration and Like Article

5. The product under consideration in the present investigation is “Viscose Staple Fibre excluding Bamboo Fibre. The product is classified under Chapter 55 of the Customs Tariff Act under Customs Sub-heading No. 550410. However, customs classification is indicative in nature and not binding on the scope of the investigation.

6. The Authority has noted as follows in the final findings of the original investigation,

“The product under consideration is “Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre”. Viscose Staple Fibre is described as “Viscose rayon staple fibre not carded/combed” under the Customs Tariff and is also known as “Rayon Fibre” in some markets. The product under consideration is classified under Custom Headings 5504.10.00. The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. Viscose Staple Fibre was the first man-made fibre, and unlike other man-made fibres, is not a synthetic fibre. It is made through wet spinning technology and is a regenerated cellulose fibre made from wood pulp, which is essentially cellulose extracted from a sustainable natural resource i.e. wood, by subjecting it to various chemical and mechanical processes. On account of its cellulosic base, viscose staple fibre properties are similar to those of natural cellulosic fibres than those of thermoplastic, petroleum based synthetic fibres such as nylon or polyester. Further, it has a distinct advantage of engineered specification and uniformity. Viscose Staple Fibre has silk-like aesthetic with superb drape, soft feel and retains rich brilliant colours. Fabrics made from it are moisture absorbent (even more than cotton), breathable, comfortable to wear, and easily dyeable in vivid colours. They do not build up static electricity, and are pill-resistant. Main strength of VSF is its versatility and ability to blend easily with nearly all other textile fibres to impart lusture, softness, absorbency and resulting comfort to the fabric made from such blends. Bamboo fibre, one of the types of Viscose Staple Fibre is excluded from the scope of this investigation. In the initiation notification, Designated Authority has specifically requested the interested parties to make their submissions with regard to exclusion of Bamboo Fibre. None of the interested parties had made any submissions in this regard.”

Since the proposed investigation is a sunset review investigation, the scope of the product under consideration is the same as that of original investigation

Like Article

7. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

8. Petitioner has claimed that there is no known difference in subject goods exported from subject countries and that produced by the Indian industry. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc.

Domestic Industry & Standing

9. M/s Grasim Industries Ltd. has provided required information as domestic industry. The Applicant is the sole Indian producer of the product under consideration. As submitted by the Petitioner Company, they have not imported the product under consideration from the subject countries during the POI. However, Petitioner Company's group has production setup in various countries including China and Indonesia [Birla Jingwai Fibres Company Limited, China and PT Indo Bharat Rayon, Indonesia]. On the basis of information furnished by the applicants, the Authority notes that no

exports have been made to India by the related exporters in subject countries during the POI. Therefore, the Authority has considered the petitioner company as domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

Initiation of sunset review

10. WHEREAS, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Period of Investigation

11. The period of investigation (POI) is April, 2014 – March 2015 (12 months) for the purpose of present investigation. The injury investigation period will however cover the periods April 2011 - March 2012, April 2012-March 2013, April 2013-March, 2014 and the POI. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

Procedure

12. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No. 14/6/2009-DGAD dated 17th May 2010 (final findings of the original investigation).

13. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

14. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street, New Delhi – 110001

15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

Time Limit

16. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis

18. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.

19. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

20. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

24. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

Non-cooperation

25. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. K. DADOO, Designated Authority